

V8. 13870
31/3/04

कार्य सरकार R-9374..... -
दे दिनांक..... को प्राप्त।
1-3-04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी

साक्ष्य वितरण एका



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-450
KM-30
Dept-200
CPB-220

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

पूरा किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2004

प्रभारी
ए० नि० ए०

सा०का०नि० 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और पदावधि) नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और पदावधि) नियम, 2004 है।

(2) ये संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) “अनुच्छेद” से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) “आयोग” से अनुच्छेद 338 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है;

(घ) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं;

(ङ) “अनुसूचित जाति” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 366 के खंड (24) में है;

(च) “उपाध्यक्ष” से आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. अर्हताएं-- (1) सदस्यों की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है ।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अध्यक्ष की नियुक्ति अनुसूचित जातियों के ऐसे प्रतिष्ठित, सामाजिक- राजनैतिक कार्यकर्ताओं में से की जाएगी जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और निःस्वार्थ सेवा के द्वारा अनुसूचित जातियों के बीच विश्वास पैदा करते हैं ;

(ख) उपाध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से नियुक्ति किए जाएंगे ;

(ग) कम से कम एक अन्य सदस्य, महिलाओं में से नियुक्त किया जाएगा ;

4. सदस्य की नियुक्ति-- इन नियमों के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्य अंशकालिक आधार पर भी नियुक्त किए जा सकेंगे ।

5. पदावधि-- (1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक सदस्य ऐसी तारीख से, जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(2) सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

6. वेतन और भत्ते-- (1) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, प्रत्येक सदस्य भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के होंगे ।

(2) प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों और अन्य सुविधाओं का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं :

परन्तु अध्यक्ष किरायामुक्त आवास का भी हकदार होगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, संसद् या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य है तो वह, यथास्थिति, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित भत्तों

से भिन्न या ऐसे भत्तों से भिन्न यदि कोई हों, किसी पारिश्रमिक का हस्तांतर नहीं होगा जो राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य, राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता के निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी निरर्हता उपगत किए बिना प्राप्त कर सकेगा ।

(4) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य भारत सरकार के सचिव को लागू दौरे के दौरान यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

7. **स्थायी या अस्थायी रिक्तियों की दशा में व्यवस्था--**(1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

(2) यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि उपाध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे अन्य सदस्य द्वारा, जैसा राष्ट्रपति निदेश दे, तब तक किया जाएगा जब तक नया उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान उपाध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

8. **आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध--**

जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है अथवा कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है अथवा किसी अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त सेवक है और किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है वहां इन नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय वेतन में से उस पेंशन की रकम और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो, पेंशन के उस भाग की रकम कम कर दी जाएगी ।

9. पदत्याग और हटाया जाना - (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2)(क) अध्यक्ष को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर ऐसे न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (ज) के अधीन उसके द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है कि अध्यक्ष को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ;

(ख) राष्ट्रपति, अध्यक्ष को, जिसके संबंध में इस उपनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है ;

(ग) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष :-

(i) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ii) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(iii) ऐसे अपराध के लिए जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता है ; या

(iv) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है या उसने अध्यक्ष की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति के उस पद पर बने रहने से अनुसूचित जातियों के हितों के लिए हानिकारक होगा,

तो राष्ट्रपति अध्यक्ष को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा :

परंतु अध्यक्ष को इस खंड के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर न दे दिया गया हो ;

(घ) यदि अध्यक्ष, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या उसकी ओर से की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह खंड (क) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

(3) राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष या सदस्य के पद से तभी हटाएगा जब वह व्यक्ति,—

(क) अनुमोचित दिवालिया है ;

(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है ;

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है ;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(च) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों के हितों के लिए हानिकारक होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

[फा. सं. 17016/28/2003-एससीडी-VI]

पी० नारायणमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2004

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 338 of the Constitution and in supersession of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Castes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 2004

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Constitution (Eighty-Ninth Amendment) Act, 2003.

2. Definition - In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) “article” means article of the Constitution;
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission;
- (c) “Commission” means the National Commission for Scheduled Castes established under article 338;
- (d) “Member” means a Member of the Commission and includes the Chairperson and the Vice-Chairperson;
- (e) the expression “Scheduled Castes” shall have the meaning assigned in clause (24) of article 366;
- (f) “Vice Chairperson” means the Vice Chairperson of the Commission.

3. Qualifications: - (1) The Members shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have had a record of selfless service to the cause of justice for the Scheduled Castes.

(2) Subject to the provisions of sub rule (1)-

- (a) The Chairperson shall be appointed from amongst eminent socio-political workers belonging to the Scheduled Castes, who inspire confidence amongst the Scheduled Castes by their very personality and record of selfless service.
- (b) The Vice-Chairperson and all other Members out of whom at least two shall be appointed from amongst persons belonging to the Scheduled Castes.

(c) At least one other Member shall be appointed from amongst women.

4. **Appointment of Members** - The Members to be appointed under these rules may be appointed on part-time basis also.

5. **Term of Office** - (1) Save as otherwise provided in these rules, every Member shall hold office for a term of three years from the date on which he/she assumes such office.

(2) The Members shall not be eligible for appointment for more than two terms.

6. **Salaries and allowance:** -

(1) Every Member shall have the rank of a Secretary to the Government of India unless otherwise specified.

(2) Every Member shall be entitled to such salaries, allowances and other facilities as admissible to a Secretary to the Government of India.

Provided that the Chairperson shall also be entitled to a rent free accommodation,

(3) Notwithstanding anything contained in sub rule (1) and (2), if the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member is a Member of Parliament, or a State Legislature he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a member appointed on part-time basis shall be entitled to traveling allowance and daily allowance during tour applicable to a Secretary to the Government of India.

7. **Arrangement in case of permanent or temporary vacancies-**

(1) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairperson.

(2) If the office of the Vice-Chairperson becomes vacant or if the Vice-Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Vice-Chairperson assumes office or the existing Vice-Chairperson resumes his office, be discharged by such other Member as the President may direct.

8. Special provision for retired persons appointed as Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission-

Where any person, being a retired judge of Supreme Court or of a High Court or a retired government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as Chairperson, Vice-Chairperson or a Member, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

9. Resignations and Removal- (1) The Chairperson and Vice-Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to the President, resign his post.

(2) (a) The Chairperson shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed by it under sub-clause (j) of clause (1) of article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson ought on any such ground to be removed.

(b) The President may suspend from office the Chairperson in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(c) Notwithstanding anything in clause (a) the President may by order remove from office the Chairperson if the Chairperson.

(i) is adjudged an insolvent; or

(ii) engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(iii) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude; or

(iv) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or has so abused the position of Chairman as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Scheduled Castes.

Provided that the Chairperson shall not be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(d) If the Chairperson is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State of

participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (a) be deemed guilty of misbehavior.

(3) The President shall remove a person from the office of Vice-Chairperson or Member, if that person, -

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude;
- (c) is in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body;
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
- (e) is without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
- (f) in the opinion of the President, has so abused the position of Vice-Chairperson or Member as to render that persons continuance in office detrimental to the interest of the Scheduled Castes:

Provided that no person shall be removed under this sub-rule until he has been given reasonable opportunity of being heard in the matter.

[F. No. 17016/28/2003-SCD-VI]

P. NARAYANA MURTHY, Jt. Secy.